की जारी पूंजी बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जा रही है ।

(vii) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों को भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) की सूचीबद्ध और अन्य योजनाओं, आईडीबीआई, आईसीआई सीआई, आईएफसीआई और सिडबी जैसी लाभ अर्जित करने वाली सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं में सावधि जमाराशियों राष्ट्रीयकृत बैंकों और लाभ अर्जित करने वाली सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं के बांडों और ख्यातिप्राप्त विश्वसनीय कम्पनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश करने के लाभप्रद अवसर उपलब्ध कराये हैं । इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रायोजक बैंकों द्वारा जारी किये जाने वाले जोखिम रहित सहभागिता प्रमाणपत्रों के जरिये अपनी आंशिक अधिशेष गैर-एसएलआर निधियों को अपने प्रायोजक बैंकों के ऋण पोर्ट-फोलियों में नियोजित करने की अनुमति प्रदान की है ।

Installation of TV Transmitter at Ghandyal, Uttar Pradesh

*5. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding setting up of new TV transmitter at Ghandyal, District Pauri-Garhwal, Uttar Pradesh;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what are the reasons for delay in the matter and by when the said TV transmitter is likely to be set up?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) Yes, Sir.

(b) Requests have been received, from time to time, from various quarters for the establishment of a TV transmitter at Ghandyal.

(c) Doordarshan projects are sanctioned subject to suitability of location, availability of resources, requisite infrastructure, and inter-se priority. Government has recently approved the setting up of the Very Low Power TV Transmitter at Ghandyal. It may take approx. 2 years for the commissioning of the transmitter.

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का पुनरुद्धार

***6. श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के पुनरुद्धार के लिये बनाई गई 2005 करोड़ रुपये की योजना को अभी अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना इस समय किस स्तर पर विचाराधीन है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन पूर्ण होने तक वस्त्र मिलों के कर्मचारियों के मासिक वेतन आदि के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो 15 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि को कब तक जारी किये जाने तथा मिलों को दिये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) वस्त्र अनुसंधान संघों ने 2005.72 करोड़ रु० के निवेश से एन.टी.सी. की 79 मिलों के आधुनिकीकरण के लिये एक योजना तैयार की थी । आधुनिकीकरण योजना 36 गैर-अर्धक्षम मिलों को 18 अर्धक्षम मिलों में पुनः संरचित करने पर विचार किया गया है । श्रम मंत्रालय की एन टी सी विषयक त्रिपक्षीय समिति ने सिफारिश की है कि वस्त्र अनुसंधान संघों के प्रस्ताव

के अनुसार एन टी सी मिलों के साथ-साथ उसकी अधिग्रहीत मिलों को आधुनिकीकरण द्वारा अर्धक्षम बनाया जा सकता है ।

एन टी सी के लिये एक सर्वांगीण सुधार योजना सरकार के विचाराधीन है । चूंकि एन टी सी के 8 सहायक निगमों के मामले औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजे ग ये हैं, इसलिये किसी भी योजना को अंतिम रूप देने के लिये उसको क्रियान्वित करने से पहले वी आई एफ आर की सहमति भी प्राप्त करनी होगी ।

(ग) और (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने जनवरी, 1995 तक की अवधि के लिये एन टी सी को मजदूरी, वेतन, बोनस आदि के भुगतान के लिये अभी तक 124 करोड़ रु० की राशि निवेष की है ।

Foreign print media entry

*7. SHRI KRISHAN LAL SHARMA:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have now decided to allow foreign print media to operate from India;

(b) if so, the names of foreign print media operators allowed to operate;

(c) what steps Government have taken to safeguard the interests of local media;

(d) whether Government have also drawn any guidelines to safeguard national interests; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) No, Sir.

(b) to (e) Do not arise.

Hike in Excise Duty

*8. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that some laundry soap manufacturers in Delhi had increased the prices of their products from 1st March, 1994 on the levy of excise duty on washing soap.

(b) whether Government are also aware that some of those manufacturers had withdrawn the excise duty hike from their prices;

(c) whether none of these manufacturers were entitled to charge the Central excise;

(d) if so. the details in this regard;

(e) the action taken or proposed to be taken by Government in the matter; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (f) It has been reported that some laundry soap manufacturers had increased their prices after 1-3-94 and some of them had, later, reduced their prices. It has also been reported that the increase in the prices were inter alia, related to increase in the cost of raw material and other inputs.

There is no legal mechanism to ensure that reduction in excise duty is fully reflected in the prices where there is no price control. If, however, a manufacturer collects any amount as representing the duty of Excise, he is obliged to deposit the same with the exchequer.

Loans to Agro-based Industries

*9. SHRI V. RAJAN CHELLAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have chalked out or propose to chalk out any program-